शेर सिंह उर्फ पार्टपा

बनाम

हरियाणा राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1592/2011)

09 जनवरी, 2015

[न्यायाधिपति विक्रमजीत सेन और न्यायाधिपति कुरियन जोसेफ]

दंड संहिता, 1860 धारा- 304 बी और 498 ए- दहेज हत्या - अभियोजन का मामला कि पीड़ित पत्नी ने शादी के एक साल के भीतर अपने पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली - अपनी मृत्यु से दो महीने पहले उसने अपने भाइयों को दहेज की मांग से जुड़ी क्रूरता के बारे में सूचित किया - दोषसिद्धि और सजा ट्रायल कोर्ट द्वारा पीड़िता के पति, देवर और ससुर को धारा 304 बी और 498 ए के तहत दोषी ठहराया गया - हाई कोर्ट ने पीड़िता के देवर और ससुर को बरी कर दिया, हालांकि दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी पति की अपील पर, आयोजित: एक बार जब अभियोजन पक्ष द्वारा दहेज हत्या के सहवर्ती तत्वों को स्थापित या दिखाया या साबित कर दिया जाता है, तो संभावना की प्रबलता के बावजूद, निर्दोषता की धारणा को आरोपी के अपराध की धारणा से बदल दिया जाता है, जिसके बाद आरोपी के कंधों पर विस्थापित होने का भारी बोझ डाल दिया जाता है। उचित संदेह से परे माना गया दोषी, न कि केवल सबूतों की प्रबलता से अभियोजन पक्ष ने यह नहीं दिखाया है और यहां तक कि संभावनाओं की प्रबलता से भी साबित नहीं किया है कि मृतक के साथ दहेज की मांग से उत्पन्न क्रूरता का व्यवहार किया गया था - एल्यूमीनियम फॉस्फेट का अंतर्ग्रहण आकस्मिक हो सकता है - अभियोजन पक्ष द्वारा दिखाए गए तथ्यों या परिस्थितियों की अपर्याप्तता या असंतोषजनक प्रकृति के कारण,

अपनी बेगुनाही साबित करने का बोझ अपीलकर्ता पर नहीं डाला गया - इस प्रकार, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया।

न्यायालय द्वारा अपील को अनुमति देते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया :-

1.1. धारा 113 बी साक्ष्य अधिनियम और धारा 304 बी आईपीसी को उनके संबंधित क़ानूनों में एक साथ पेश किया गया था और इसलिए, आमतौर पर यह माना जाना चाहिए कि संसद ने जानबूझकर इस प्रावधान को दूसरों से अलग करने के लिए धारा 304 बी में 'मान लेना' शब्द का इस्तेमाल किया था। हालाँकि, वास्तविकता में, इन प्रावधानों को एक समझदार और कानूनी रूप से स्वीकार्य अर्थ देना लगभग असंभव है, जब तक कि 'दिखाया गया' शब्द 'साबित' के पर्याय के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है और 'अनुमान' शब्द को 'माने गए' शब्द के साथ स्वतंत्र रूप से विनिमेय नहीं किया जाता है। आईपीसी की धारा 304 बी में 'दिखाया गया' शब्द का अर्थ वास्तव में 'साबित' करना है। 'जल्द' शब्द को धारा 304 बी में जगह मिलती है; लेकिन प्राथमिकता यह होगी कि इसके उपयोग की व्याख्या दिनों या महीनों या वर्षों के संदर्भ में न की जाए, बल्कि यह आवश्यक रूप से इंगित किया जाए कि दहेज की मांग पुरानी या अतीत की भूल नहीं होनी चाहिए, बल्कि धारा 304 बी के तहत मृत्यु का निरंतर कारण होनी चाहिए। या आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या। एक बार जब अभियोजन पक्ष द्वारा इन सहवर्ती लोगों की उपस्थिति स्थापित या दिखा दी जाती है या साबित कर दी जाती है, यहां तक कि संभावना की प्रबलता से भी, निर्दोषता की प्रारंभिक धारणा को आरोपी के अपराध की धारणा से बदल दिया जाता है, जिसके बाद सबूत का भारी बोझ उस पर स्थानांतरित हो जाता है और उससे आवश्यकता होती है उचित संदेह से परे उसके अपराध को खारिज करने वाले साक्ष्य प्रस्तुत करना। [पैरा 14) [45-एफ, जी; 46-डी; एफ-एच]

1.2. सबूत का भार पति पर होता है कि वह अपने समझे गए दोषी को खारिज करके अपनी बेगुनाही साबित करे, और इससे पहले अभियोजन पक्ष को केवल तीन कारकों की उपस्थिति को साबित करना होगा, अर्थात (i) असामान्य परिस्थितियों में एक महिला की मृत्यु (ii))उसकी शादी के सात साल के भीतर, और (iii) कि मृत्यु का दहेज की किसी भी मांग से जुड़ी क्रूरता से सीधा संबंध था। दूसरा पहलू यह है कि पति के कंधों पर वास्तव में एक भारी बोझ है, जिसमें उसकी समझी गई दोषीता को उचित संदेह से परे विस्थापित और पलटना होगा।धारा '304 बी में आरोपी को अपने खिलाफ सबूत देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उचित संदेह से परे उसके समझे गए अपराध को खारिज करने का कठिन बोझ डाला गया है। संभाव्यता की प्रधानता के लिए पति की ज़िम्मेदारी को कम करना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे धारा 304 बी में व्यक्त किए गए अपराध को नष्ट कर दिया जाएगा, और इस तरह की अचूक व्याख्या संसद के इरादों और उद्देश्यों को पराजित और बेअसर कर देगी। कहने की आवश्यकता केवल यह है कि यदि पति उन तथ्यों को साबित करता है जो उचित संदेह से परे दर्शाते हैं कि वह अपनी पत्नी की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट से नहीं कर सकता था या असामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु में किसी भी तरह से शामिल नहीं था, तो वह धारा 304 बी के तहत दोषी नहीं होगा।[पैरा 17] [49-ई-जी 50-बी-सी, ई-एफ]

2. मौलिक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो न्यायालय को खुद से पूछना है और इसका ठोस उत्तर ढूंढना है, वह यह है कि क्या यह साक्ष्य प्रमुख रूप से यह साबित करता है कि अपीलकर्ता ने दहेज की मांग से संबंधित मृतक के साथ क्रूरता का व्यवहार किया था। यह तभी है जब उत्तर इसमें है सकारात्मक बात यह है कि अदालत को अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों को तौलना होगा ताकि उचित संदेह से परे उसके दोषी अपराध की धारणा को खारिज किया जा सके। आत्महत्या के समय मृतक गर्भवती थी और केवल असाधारण और भारी कारकों ने ही उसे अपने अजन्मे बच्चे के साथ अपनी

जान लेने के लिए प्रेरित किया होगा। तथ्य यह है कि उसने ऐसा किया। उसे यह चरम और भयानक कदम उठाने के लिए किसने प्रेरित या मजबूर किया यह एक रहस्य बना रहेगा, क्योंकि यह अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया है या दिखाया भी है कि दहेज की मांग से संबंधित उसके साथ इतनी क्रूरता की गई, जिसके कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ी। . सामान्य तौर पर दहेज की माँग तब की जाती है जब विवाह पर सहमति हो जाती है और निश्चित रूप से विवाह के समय इसे दोहराया जाता है और ऐसी माँगें विवाह के कुछ वर्षों तक जारी रहती हैं। सामान्य तौर पर, यदि किसी महिला पर अत्याचार और उत्पीड़न किया जा रहा है, तो वह इस स्थिति से पीछे नहीं हटेगी और निश्चित रूप से बार-बार अपने परिवार को सूचित करेगी।ऐसा खासतौर पर इससे पहले होता है कि वह अपनी जान लेने जैसा चरम कदम उठा ले। दहेज की मांग, पंचायत और 'जीएस' की उपस्थिति और ज्ञान के संबंध में पीडब्लू4 और पीडब्लू7 के बयानों के बीच विसंगतियां और विरोधाभास हैं।इन्हीं कारणों से अभियोजन पक्ष ने यह नहीं दिखाया/प्रस्तुत किया है और न ही संभावनाओं की प्रबलता से भी साबित किया है कि मृतक के पास दहेज की मांग से उत्पन्न या उस पर आधारित क्रूरता का व्यवहार किया गया है। यह संभावना है कि एल्यूमीनियम फॉस्फेट का अंतर्ग्रहण आकस्मिक हो सकता है। आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपनी जांच में अपने बचाव का विवरण पेश किया। यह ऐसा मामला नहीं है जहां उन्होंने अदालत द्वारा उनसे पूछे गए सभी सवालों से इनकार कर दिया। अभियोजन पक्ष द्वारा दिखाए गए तथ्यों या परिस्थितियों की अपर्याप्तता या असंतोषजनक प्रकृति के कारण, उसे साबित करने का भार निर्दोषता अपीलकर्ता को हस्तांतरित नहीं हुई है। अपीलकर्ता को दोषीठहराने और दंडित करने के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाता है। [पैरा 22,23] [53-बी-एच; 54-बी-सी]

नारायणमूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य 2008 (8) एससीआर 403: (2008) 16 एससीसी 512; दुर्गा प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2010 (7) एससीआर 104: (2010) 9 एससीसी 73; पंजाब राज्य बनाम इकबाल सिंह 1991 (2) एससीआर 790 : 1991 (3) एससीसी 1;जसविंदर सैनी बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार) 2013 (7) एससीआर 340 :2013 (7) एससीसी 256; पठान हुसैन बाशा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2012 (7) एससीआर 290: (2012) 8 एससीसी 594; त्रावणकोर राज्य कोचीन बनाम शनमुघा विलास काजू फैक्ट्री 1954 एससीआर 53: एआईआर 1953 एससी 333; तमिलनाडु राज्य बनाम अरूरन शुगर्स लिमिटेड 1996 (8) पूरक एससीआर 193:(1997) 1 एससीसी 326; मीर मोहम्मद उमर और सुब्रमण्यम बनाम तमिलनाडु राज्य (2009) 14 एससीसी 415; अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य 2010 (7) एससीआर 1119: 2010 (12) एससीसी 350; नल्लम वीरा सत्यानंदम बनाम लोक अभियोजक 2004 (10) एससीसी 769; मिठू बनाम पंजाब राज्य 1983 (2) एससीआर 690 : एआईआर 1983 एससी 473; पी.एन. कृष्ण लाल बनाम केरल सरकार 1994(5) सप्ल. एससीआर 526:1995 अनुपूरक (2) एससीसी 187 - संदर्भित

संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी; द ब्लैक लॉ डिक्शनरी (5 वाँ संस्करण) - संदर्भित

वाद कानून के संदर्भित

2008(8)एस सी आर 403	संदर्भित	पैरा 4
2010(7)एस सी आर 104	संदर्भित	पैरा 4
1991(2) एस सी आर 790	संदर्भित	पैरा 10
2013(7)एस सी आर 340	संदर्भित	पैरा 10
2012(7)एस सी आर 290	संदर्भित	पैरा 11
1954 एस सी आर 53	संदर्भित	पैरा 14

1996(8)पूरक एस सी आर 193	संदर्भित	पैरा 14
(2009)14 एस सी सी 415	संदर्भित	पैरा 15
2010(7)एस सी आर 1119	संदर्भित	पैरा 16
2004(10)एस सी सी 769	संदर्भित	पैरा 16
1983(2)एस सी आर 690	संदर्भित	पैरा 17
1994(5)पूरक एस सी आर 526	संदर्भित	पैरा 17

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 1592/2011

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, एकल न्यायाधीश की आपराधिक अपील संख्या 894 एसबी -2000 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 16.12.2010 से।

अंकुर मित्तल अपीलार्थी की ओर से।

राव रंजीत प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति विक्रमजीत सेन द्वारा पारित किया गया था-

1. यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 16.12.2010 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें अपील को खारिज कर दिया गया है और धारा 304 बी और 498 ए के तहत विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ पारित दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई है। भारतीय दंड संहिता के. मृतक हरजिंदर कौर और आरोपी-अपीलकर्ता के बीच शादी 22.2.1997 को हुई थी। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि उसकी मृत्यु से दो महीने पहले, जब वह अपने माता-पिता के घर गई थी, तो मृतक ने उसे इसकी जानकारी दी थी।

उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसके साथ दहेज की मांग को लेकर भाइयों द्वारा क्रूरता की गई। इसके बाद, उन्होंने यह जानकारी अपने चाचा-शिकायतकर्ता अंग्रेज सिंह को दी कि आरोपी और उसका परिवार मोटरसाइकिल और फ्रिज की मांग को लेकर उसे परेशान कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने उसे इस आश्वासन के साथ अपने वैवाहिक घर लौटने की सलाह दी कि उसके भाइयों की शादी पर एक मोटरसाइकिल और एक फ्रिज की व्यवस्था की जाएगी। दिनांक 7.2.1998 को राजवंत सिंह नाम के व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को सूचित किया कि मृतक ने गांव दानोली में अपने वैवाहिक घर में कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। शिकायतकर्ता, मृतक के भाइयों और गांव के अन्य सदस्यों के साथ, मृतक के वैवाहिक घर पहुंचे और उसकी मृत्यु की पुष्टि करने के बाद, अगले दिन यानी 8.2.1998 को प्राथमिकी दर्ज कराई।

2. कुल मिलाकर, चार आरोपी व्यक्ति, अर्थात् अपीलकर्ता/शेर सिंह (पति), देविंदर सिंह (देवर) जरनैल सिंह (ससुर), और सुखविंदर कौर (सास) विद्वान सत्र न्यायाधीश, कमल द्वारा आईपीसी की धारा 304 बी और 498 ए के तहत मुकदमा चलाया गया। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें धारा 304 बी के तहत सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई; और तीन साल के लिए कठोर कारावास और 5,000/- रुपये का जुर्माना देना होगा और इस तरह के जुर्माने का भुगतान न करने पर, धारा 498 ए के तहत छह महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

3. चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष दो अलग-अलग अपीलें दायर की गईं, एक देविंदर सिंह (जीजा) द्वारा जरनैल सिंह (ससुर) के साथ और दूसरी अपीलकर्ता द्वारा। उच्च न्यायालय ने देविंदर सिंह और जरनैल सिंह द्वारा दायर

अपील को स्वीकार कर लिया और उन्हें इस टिप्पणी के साथ बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके द्वारा की गई किसी भी यातना को साबित करने में विफल रहा है और इसलिए, आईपीसी की धारा 304 बी और 498 ए लागू नहीं होती हैं। स्पष्ट रूप से, ट्रायल कोर्ट के विपरीत, उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 304 बी के लिए भी अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे 'साबित' करने की आवश्यकता है

इसके विपरीत, पति के रिश्तेदारों की सहभागी भूमिका को दोषी मानने की प्रस्तावना के रूप में 'दिखाना' चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा यह भी देखा गया कि ऐसे मामलों में इस तथ्य की अनदेखी करते हुए परिवार के सभी सदस्यों को इसमें शामिल करने की प्रवृत्ति होती है। वे अलग-अलग रहते थे। हालाँकि, अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि यह अभियुक्त/अपीलकर्ता को यह बताना था कि उसकी पत्नी हरजिंदर कौर की अप्राकृतिक मौत वैवाहिक घर में उसके साथ हुई क्रूरता के कारण नहीं हुई थी और वह ऐसा करने में विफल रहा है।

4. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द किया जा सकता है क्योंकि विद्वान सत्र न्यायालय की एक विशिष्ट खोज है कि रिकॉर्ड पर इस आशय का कोई सकारात्मक सबूत नहीं है कि आरोपी व्यक्ति कभी एक मोटरसाइकिल और एक फ्रिज की मांग उठाई और नीचे की दोनों अदालतें गवाही में विसंगतियों को पूरी तरह से समझने में विफल रही हैं

पीडब्लू 4 और 7, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि दोनों ही इच्छुक गवाह थे। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने दलीलों और सबूतों के एक ही सेट पर, अन्य आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् देविंदर सिंह (जीजा) और जरनैल सिंह (ससुर) को बरी करना उचित नहीं ठहराया, जबकि अपीलकर्ता को दोषी ठहराना। इस तर्क के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने नारायणमूर्ति बनाम

कर्नाटक राज्य (2008) 16 सेकंड 512 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित नहीं किया है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले, मृतक दहेज की किसी मांग के संबंध में किसी क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार हुआ हो। दुर्गा प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) 9 एससीसी 73 से समर्थन लिया गया है।

5. सबसे पहले हम उस विषय पर संसद द्वारा पारित कानून की रूपरेखा का संक्षेप में विश्लेषण करेंगे, जिस पर हम वर्तमान में विचार कर रहे हैं। लोलुप और अतृप्त दहेज की माँगों के कारण विवाहित महिलाओं को मौत की सजा दिए जाने की घटनाओं के व्यापक प्रसार का सामना करना पड़ा, और/या दुल्हनों को अपने पति और उसके परिवार द्वारा उनके साथ की जाने वाली क्रूरता के कारण अपनी जान लेने के लिए प्रेरित किया गया। दहेज की अपेक्षाएं, दहेज लेने और देने की सामाजिक बुराई को खत्म करने के प्रयास में संसद ने दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'दहेज अधिनियम') अधिनियमित किया। इसकी धारा 2 'दहेज' को परिभाषित करती है, जिसमें विवाह के समय एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई या देने के लिए सहमत कोई भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा शामिल है। धारा 3 दहेज देना या लेना या देने या लेने के लिए उकसाना दंडनीय बनाती है; अपराध के लिए सज़ा पांच साल से कम नहीं होगी, और 15,000/- रुपये का जुर्माना या ऐसे दहेज के मूल्य की राशि, जो भी अधिक हो। इसकी उपधारा (2) स्पष्ट रूप से दिए गए उपहारों के संबंध में बहिष्करण बनाती है

विवाह के समय, बशर्ते कि वे प्रथागत प्रकृति के हों और संबंधित पक्षों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनका मूल्य अत्यधिक न हो। यह अनुभाग विवाह के अवसर पर प्राप्त उपहारों की एक सूची तैयार करने का भी आदेश देता है। धारा 4 दहेज की मांग करना भी दंडनीय बनाती है और यदि दहेज लेने या देने के लिए कोई समझौता किया जाता है, तो धारा 5 इसे शून्य बना देती है। धारा 6 स्पष्ट करती

है कि जहां कोई भी दहेज उस महिला के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसके विवाह के संबंध में यह दिया गया है, तो इसे विवाह के तीन महीने या दहेज की प्राप्ति के भीतर उसे हस्तांतरित किया जाना चाहिए। हालाँकि, इस क़ानून के पारित होने से दहेज की माँगों का संकट समाप्त नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप संसद को एक बार फिर अपना ध्यान इस ओर लगाना पड़ा कि समाज को इस हानिकारक प्रथा से मुक्त करने के लिए क्या आवश्यक है।

6. जैसा कि आपराधिक कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1983 [1983 का अधिनियम 46] के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अवलोकन से स्पष्ट है, संसद दहेज हत्याओं की बढ़ती संख्या से चिंतित रही। इस कानून द्वारा अध्याय XX को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में पेश किया गया था, जिसमें एकान्त धारा 498 ए शामिल थी, ताकि "न केवल दहेज हत्या के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके, बल्कि विवाहित महिलाओं के साथ उनके ससुराल वालों द्वारा क्रूरता के मामलों से भी प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।" स्पष्टतः, इस धारा में 'दहेज' शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है। संक्षेप में, 'संशोधन पत्नी के प्रति वैवाहिक क्रूरता को एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय बनाता है जिसे जुर्माने के साथ तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 498ए का स्पष्टीकरण बी को परिभाषित करता है स्पष्टीकरण के खंड (ए) में 'क्रूरता' का अर्थ पहले जानबूझकर किया गया आचरण है जो महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकता है या उसके जीवन को गंभीर चोट या खतरा पैदा कर सकता है। चूंकि इसमें दहेज का कोई संकेत नहीं है, इसलिए यह क्रूरता में परिवर्तित हो जाता है, जो कि आम तौर पर पत्नी को अपने विवाह को एक आपराधिक कृत्य में विघटित करने की मांग करने का अधिकार देना, संसद ने उचित रूप से विषय अपराध को केवल महिलाओं पर होने वाली क्रूरता तक सीमित कर दिया है, क्योंकि उनकी मुक्ति, सार्थक अर्थ में, काफी हद तक एक मृगतृष्णा बनी हुई है। कोई केवल आशावादी

रूप से आशा कर सकता है कि साक्षरता में वृद्धि होगी महिलाओं के बीच, साथ ही हिंदू कानून में बेटी को उसके पिता की संपत्ति में हिस्सा देने के संशोधन से भी जल्द ही इस समस्या का अंत हो जाएगा। चूंकि हम इस अपील में स्पष्टीकरण के खंड (ए) के दायरे में आने वाली घटनाओं से चिंतित नहीं हैं, इसलिए हम स्वीप और इरादे और उसमें निहित संभावित विसंगतियों पर कोई और प्रतिबिंब दर्ज करने से बचेंगे क्योंकि हमारी ओर से इस तरह के अभ्यास से बचा जा सकेगा। प्रासंगिक उक्ति के बोझिल बोझ के कारण, जो हमेशा भ्रम का कारण बनता है। दूसरे मोटे तौर पर कहा गया है, आईपीसी की धारा 498ए के स्पष्टीकरण के खंड (बी) में किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए उसके या उसके रिश्तेदारों पर दबाव डालने की दृष्टि से महिला के साथ किए गए उत्पीड़न को दर्शाया गया है। हालाँकि यह खंड 'दहेज' शब्द का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य इस घृणित सामाजिक बहिष्कार का मुकाबला करना है। 1983 के अधिनियम 46 में एक साथ किसी महिला की शादी के सात साल के भीतर आत्महत्या या मृत्यु से संबंधित सीआरपीसी की धारा 174(3) में बदलाव शामिल किए गए; इसने दुर्भाग्यपूर्ण महिला के शरीर की निकटतम सिविल सर्जन द्वारा जांच अनिवार्य कर दी। इसके अलावा, धारा 113ए को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में पेश किया गया था। [हालांकि वर्तमान संदर्भ के लिए प्रासंगिक नहीं है, यह मार्मिक है कि भले ही धारा 113 इसकी सक्रिय जांच के अधीन थी, संसद ने मौजूदा और मौजूदा को हटाना जरूरी नहीं समझा। पूरी तरह से अप्रासंगिक धारा 113 जो 'ब्रिटिश' क्षेत्र को किसी भी 'मूल राज्य' को सौंपने की बात करती है]। धारा 113ए, 1983 के अधिनियम 46 के खंड 7 द्वारा साक्ष्य अधिनियम में पेश की गई, यह निर्दिष्ट करती है कि जब सवाल यह है कि क्या किसी महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उसके पति या उसके रिश्तेदार ने उकसाया था और यह दिखाया गया है कि उसने आत्महत्या की है उसकी शादी की

तारीख से सात साल की अवधि और उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार ने उसके साथ क्रूरता की थी, अदालत मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मान सकती है कि ऐसी आत्महत्या को उसके पति ने उकसाया था या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा।

7. तीन साल की छोटी सी अवधि के भीतर संसद ने 1986 के अधिनियम 43 को अधिनियमित करके दहेज अधिनियम के साथ-साथ आईपीसी में संशोधन करके कानून को और अधिक कठोर और प्रभावी बनाने की आवश्यकता महसूस की। इन संशोधनों ने, अन्य बातों के साथ-साथ अपराधों का निपटारा किया। दहेज अधिनियम में कुछ उद्देश्यों के लिए संज्ञेय और उन्हें गैर-जमानती के साथ-साथ गैर-शमनयोग्य भी बनाया गया है। दहेज अधिनियम की धारा 8ए की शुरूआत से संबंधित व्यक्ति को यह साबित करने के लिए जिम्मेदार बनाकर कि उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, दहेज लेने या लेने या मांगने के लिए प्रेरित करने के अभियोजन के संबंध में सबूत का बोझ उलट दिया गया था। समसामयिक धारा आईपीसी में 304बी को शामिल किया गया था। नई जोड़ी गई धारा में कहा गया है कि जहां एक महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है या उसकी शादी के सात साल के भीतर सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में होती है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में अपने पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार हुई हो, ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा, और ऐसे पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा। उपधारा (2) इस अपराध को कारावास से दंडनीय बनाती है जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी और जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 113बी को आगे साक्ष्य अधिनियम में शामिल किया गया; [एक बार फिर मौजूदा धारा 113 के रूप में मुरझाए हुए उपांग को बनाए रखने की

निरर्थकता, यदि बदनामी नहीं तो, को नजरअंदाज करना, और आगे चलकर कालभ्रम को कायम रखना।] जो भी हो, नई शुरू की गई धारा 113 बी में कहा गया है कि जब सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने अपराध किया है एक विवाहित महिला की मृत्यु और यह दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले ऐसी महिला पर ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था या दहेज की किसी मांग के संबंध में, अदालत यह मान लेगी कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज हत्या की है। स्पष्टीकरण दहेज हत्या की परिभाषा के लिए आईपीसी की एक साथ जोड़ी गई धारा 304 बी की ओर इशारा करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस धारा में उल्लिखित व्यक्ति उसका पति या उसके पति का कोई रिश्तेदार है। यह उल्लेखनीय है कि जहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए अदालत को अपनी पत्नी की आत्महत्या के लिए पति के उकसाने के मामले में अनुमान लगाने का अधिकार देती है, वहीं संसद ने अदालत को ऐसी स्थिति में धारा 113 बी के तहत कम से कम प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का आदेश दिया है। दहेज हत्या. हमें ऐसा लगता है कि जहां एक पत्नी को आत्महत्या के चरम कदम के लिए प्रेरित किया जाता है, वहां इसे न्यायालय के विवेक पर छोड़ने के बजाय अपने पति की सक्रिय भूमिका निभाना उचित होगा।

8. किसी महिला की शादी के सात साल के भीतर मृत्यु से संबंधित कानूनी व्यवस्था में अन्य बातों के साथ-साथ कई विशेषताएं हैं:

(i) "दहेज" का अर्थ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 2 में रखा गया है।

(ii) दहेज हत्या को आईपीसी की धारा 304 बी में सभी उद्देश्यों के लिए परिभाषित किया गया है। यह सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु को बाहर रखता है।

(iii) यदि मृत्यु जलने या शारीरिक चोट के कारण, या सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य कारण से होती है, और यह शादी के सात साल के भीतर होती है और, यह 'साबित' के विपरीत 'दिखाया' जाता है कि उसकी मृत्यु से तुरंत पहले उसे प्रताड़ित किया गया था। यदि उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न किया जाता है, और क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग से जुड़ा है तो यह दहेज मृत्यु होगी, और पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।

(iv) निवारक निरोध न्यायशास्त्र से उधार लेने के लिए - दहेज की मांग से उत्पन्न क्रूरता और एक युवा विवाहित महिला की मृत्यु के बीच एक जीवंत संबंध होना चाहिए, जैसा कि "उसकी मृत्यु से तुरंत पहले" शब्दों द्वारा इंगित करने की कोशिश की गई है। धारा 304 बी को अमल में लाना; यदि उक्त क्रूरता असामयिक और असामान्य मृत्यु के निकट जारी नहीं रहती है तो लाइव लिंक स्पष्ट रूप से टूट जाएगा। इसे समय की सीमा में सीमित नहीं किया जा सकता; अपील दायर करने में देरी को माफ करने के संदर्भ में इस न्यायालय का प्रश्न - मिनट और सेकंड क्यों नहीं - उचित बना हुआ है।

(v) मृत महिला के शरीर को निकटतम सिविल सर्जन द्वारा जांच के लिए भेजा जाना चाहिए।

(vi) एक बार जब ऊपर (iii) में सूचीबद्ध तत्व मौजूद हो जाते हैं तो पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।

(vii) इस 'समझौते' के परिणाम और प्रभाव यह होंगे कि अभियोजन पक्ष को और कुछ भी साबित नहीं करना पड़ेगा, और यह पति या उसके संबंधित रिश्तेदार पर है कि सबूत का बोझ धारा 113 बी में माना गया है, जिसे जगह मिलती है साक्ष्य अधिनियम का अध्याय VII। यह अध्याय पहले 'सबूत के बोझ' और फिर "अनुमान" को कवर करता है, दोनों निरंतर बिस्तर-साथी हैं। वर्तमान संदर्भ में मृत्यु की जिम्मेदारी को समझना या मानना पर्यायवाची है।

9. मृत्यु आकस्मिक, आत्मघाती या मानववध हो सकती है। पहला प्रकार एक त्रासदी है और कोई भी आपराधिक पहलू तब तक सामने नहीं आता जब तक कि वैधानिक रूप से ऐसा तैयार न किया गया हो, जैसा कि धारा 304 ए में है; लेकिन वहां भी दोषी वह व्यक्ति है जो वास्तव में मौत का कारण बना। हमें ऐसा लगता है कि आईपीसी की धारा 304 बी, हालांकि यह "सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी महिला की मौत" को भी अपने दायरे में लेती है, दुर्घटनाओं के रूप में हत्याओं को कवर करने का प्रयास करती है। उचित रूप से, एक विवाहित महिला की आत्महत्या की मौत जो उसके पति द्वारा क्रूरता से की गई थी, जहां उसकी मृत्यु दहेज की मांग के संबंध में शादी के सात साल के भीतर हुई थी, आईपीसी की धारा 304 बी और/या 306 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए और सजा दी जानी चाहिए। . हालाँकि, यदि पति द्वारा विश्वासघाती उत्पीड़न और क्रूरता को निर्णायक रूप से साबित कर दिया गया है कि दहेज की मांग के आधार पर उसके क्रूर व्यवहार के साथ इसका कोई कारणात्मक संबंध नहीं है, तो ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं जैसा कि भगवान दास बनाम करतार सिंह (2007)11 एससीसी 205 में आयोजित किया गया था। हालाँकि धारा 306 की पहुँच के संबंध में कुछ आपत्तियाँ बनी रह सकती हैं।

10. यह पहले से ही अनुभवजन्य रूप से स्पष्ट है कि अभियोजन सर्वत्र और कर्तव्य की उपेक्षा में है, एक असामान्य मौत के मामले में यदि एक युवा दुल्हन धारा 304 बी के तहत अपने आरोपों को सीमित कर देती है क्योंकि सबूत प्रदान करने का दायित्व उसके लिए कम से कम बोझिल हो जाता है; यह वह महत्व है जो एक विचारणीय प्रावधान से जुड़ा है। लेकिन, सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी भी मृत्यु में, जैसा कि मामले की परिस्थितियों की मांग है, हमें धारा 302 या धारा 306 का हवाला न देने का कोई औचित्य नहीं दिखता है। अन्यथा, मृत्यु तार्किक रूप से आकस्मिक मृत्यु की श्रेणी में आएगी। केवल धारा 498ए को शामिल करना पर्याप्त नहीं है क्योंकि सज़ा अपेक्षाकृत हल्की है। यदि इन प्रावधानों को ट्रिगर करने वाली परिस्थितियाँ प्रबल होती हैं, तो मानवहत्या की मृत्यु धारा 302 और 304बी के तहत प्रभार्य और दंडनीय है। इस न्यायालय ने इस स्थिति को बार-बार दोहराया है, जिसमें पंजाब राज्य बनाम इकबाल सिंह, 1991 (3) एससीसी 1 और हाल ही में जसविंदर सैनी बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार) 2013 (7) एससीसी 256 शामिल है।

11. निर्दोषता की धारणा, दोषी माने जाने और सबूत के बोझ के पहलू पर कुछ संदेह बने हुए हैं। हमारे विद्वान भाइयों में से एक ने पठान हुसैन बाशा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2012) 8 एससीसी 594 में अपने द्वारा लिखे गए पिछले फैसले से बड़े पैमाने पर निष्कर्ष निकालने के बाद (लेकिन ऐसा संकेत दिए बिना) दो राय व्यक्त की है - (ए) कि अनुच्छेद 20 भारत के संविधान में एक संदिग्ध के पक्ष में निर्दोषता की धारणा शामिल है और, (बी) कि कल्पना मानने की अवधारणा शायद ही आपराधिक न्यायशास्त्र पर लागू होती है। इन दोनों निष्कर्षों के तार्किक परिणाम से धारा 8 ए को खारिज कर दिया जाएगा। दहेज अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम की धारा"113बी, और संभवतः आईपीसी की धारा 304बी, लेकिन कोई भी निर्णय ऐसा नहीं करता है। जहां

तक पहले निष्कर्ष का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद 20 को पुन: प्रस्तुत करना पर्याप्त है:

> "20. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण.-
>
> (1) किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित कार्य के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, न ही उस पर कानून के तहत लगाए गए जुर्माने से अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। अपराध के घटित होने के समय लागू।
>
> (2) किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा।
>
> (3) किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।"

भले ही निर्दोषता की धारणा की अवधारणा के लिए कोई संवैधानिक संरक्षण नहीं हो सकता है, यह सभी सामान्य कानून कानूनी प्रणालियों में इतनी गहराई से निहित है कि भारत में भी इसे खत्म नहीं किया जा सकता है, इस तरह कि इस धारणा से प्रस्थान या विचलन वैधानिक मंजूरी की मांग करता है .दहेज कानून की त्रयी ने यही स्थापित करने का प्रयास किया है।

12. हमारी राय में, यह मूर्खता से परे है कि जहां एक ही शब्द का उपयोग किसी अनुभाग और/या किसी क़ानून के विविध खंडों में किया जाता है, तो उसका वही अर्थ लगाया जाना चाहिए, जब तक कि अन्यथा करने के लिए बाध्यकारी कारण न हों। अग्रभाग वह है जहां अलग-अलग शब्दों को निकटता में, या एक ही खंड में, या एक ही अधिनियम में नियोजित किया जाता है, यह धारणा होनी चाहिए कि विधायिका का

उद्देश्य उन्हें असमान स्थितियों को चित्रित करना, और असमान और विविध प्रभावों को चित्रित करना है। इसलिए आम तौर पर संसद यह आदेश देने का प्रस्ताव नहीं कर सकती थी कि धारा 304 बी में "दिखाया गया" शब्द का प्रयोग करने के बावजूद, अभियोजन पक्ष को तथ्यों के एक महत्वपूर्ण अनुक्रम के अस्तित्व को "साबित" करना चाहिए। सवाल यह है कि क्या इन दोनों शब्दों को पर्यायवाची माना जा सकता है। हमें ऐसा लगता है कि यदि अभियोजन पक्ष को यह साबित करने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ हमेशा उचित संदेह से परे होता है, कि दहेज हत्या की गई है, तो एक जोखिम है कि प्रावधान में निर्धारित उद्देश्य को सिफर तक कम किया जा सकता है। वैधानिक व्याख्या की इस पद्धति को असाधारण मामलों को छोड़कर लगातार अस्वीकृत और अस्वीकृत किया गया है, जहां वाक्यविन्यास विषय प्रावधानों के कुछ शब्दों को पढ़ने या पढ़ने की अनुमति देता है।

13. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए में संसद ने पत्नी की आत्महत्या के मामले में पति और उसके परिवार के सदस्यों को दोषी माना है। गौरतलब है कि धारा 113 बी में, जो स्पष्ट रूप से दहेज हत्याओं को संदर्भित करती है, संसद ने फिर से "अनुमान" शब्द का प्रयोग किया है। हालाँकि, काफी हद तक ऐसी ही परिस्थितियों में, पत्नी की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में, संसद ने धारा 304 बी में पति और उसके परिवार के सदस्यों को "दोषी" माना है। संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी "अनुमान" शब्द को इस प्रकार परिभाषित करती है: माना जाता है कि यह सत्य है, मान लिया जाए; जबकि "माननना" इस प्रकार है: सम्मान करना, विचार करना; और जबकि "दिखाएँ" इस प्रकार है: इंगित करें और सिद्ध करें। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी (5 वां संस्करण) "शो" शब्द को साक्ष्य द्वारा स्पष्ट या स्पष्ट करने, साबित करने के रूप में परिभाषित करता है; "माना गया" जैसे - माननना, विचार करना, निर्णय करना, विश्वास करना, निंदा करना, निर्धारित करना, ऐसा समझा जाना मानो सत्य है; "माननना" जैसे- विश्वास करना या

स्वीकार करना संभावित साक्ष्य; और "अनुमान", ब्लैक के अनुसार, "कानून का एक नियम है, वैधानिक या न्यायिक, जिसके द्वारा एक बुनियादी तथ्य की खोज अनुमानित तथ्य के अस्तित्व को जन्म देती है, जब तक कि अनुमान का खंडन नहीं किया जाता है।" द कॉन्साइज डिक्शनरी ऑफ लॉ, ऑक्सफोर्ड पेपरबैक्स में सबूत के बोझ की यह व्यापक लेकिन संक्षिप्त परिभाषा है जो पुनरुत्पादन के योग्य है:

> "सबूत का भार: किसी मुद्दे पर किसी तथ्य या तथ्यों को साबित करने के लिए मुकदमेबाजी में एक पक्ष का कर्तव्य। आम तौर पर सबूत का बोझ उस पक्ष पर पड़ता है जो किसी विशेष तथ्य (अभियोजन या वादी) की सच्चाई पर जोर देता है। एक अंतर है प्रेरक (या कानूनी) बोझ के बीच खींचा गया है, जो उस पक्ष द्वारा उठाया जाता है जो कानून के मामले में मामले को खो देगा यदि वह मामले में तथ्य साबित करने में विफल रहता है; और साक्ष्य बोझ (साक्ष्य जोड़ने का बोझ या आगे बढ़ने का बोझ) }, जो यह दर्शाने का कर्तव्य है कि किसी मुद्दे को उठाने या न होने के बारे में तथ्य की तिकड़ी के विचार के लिए उपयुक्त मुद्दे को उठाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।"

सामान्य नियम यह है कि प्रतिवादी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए; इसलिए यह अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह अपराध के दोषपूर्ण कार्य और आपराधिक मनःस्थिति दोनों को स्थापित करके अपना मामला साबित करे। इसे यह दिखाने के लिए पहले साक्ष्य संबंधी बोझ को पूरा करना होगा कि उसके आरोपों का समर्थन करने के लिए कुछ है। यदि यह इस बोझ को संतुष्ट नहीं कर सकता है तो बचाव पक्ष प्रस्तुत कर सकता है या न्यायाधीश निर्देश दे सकता है कि जवाब देने के लिए कोई मामला नहीं है, और न्यायाधीश को जूरी को बरी करने का निर्देश देना चाहिए। साक्ष्य के साक्ष्य के बोझ को पूरा करने के लिए

अभियोजन पक्ष कभी-कभी तथ्य की धारणाओं पर भरोसा कर सकता है (उदाहरण के लिए यह तथ्य कि एक महिला को संभोग के दौरान हिंसा का शिकार होना पड़ा, सामान्यतः एक धारणा बनेगी बलात्कार के आरोप का समर्थन करने और यह साबित करने के लिए कि उसने सहमति नहीं दी थी)। हालाँकि, यदि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के लिए एक आधार स्थापित कर लिया है, तो उसे अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करके प्रेरक बोझ को संतुष्ट करना जारी रखना चाहिए (उचित संदेह से परे सबूत देखें)। न्यायाधीश का यह कर्तव्य है कि वह जूरी को स्पष्ट रूप से बताए कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला साबित करना होगा और उसे इसे उचित संदेह से परे साबित करना होगा; यदि वह यह स्पष्ट निर्देश नहीं देता है, तो प्रतिवादी बरी होने का हकदार है।

सामान्य नियम के कुछ अपवाद हैं कि सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर है। मुख्य अपवाद इस प्रकार हैं. (1) जब प्रतिवादी अपराध के तत्वों (दोषपूर्ण कार्य और आपराधिक मनःस्थिति) को स्वीकार करता है, लेकिन एक विशेष बचाव की याचना करता है, तो अपने बचाव को साबित करने का साक्ष्यात्मक बोझ उस पर होता है। ऐसा हो सकता है, उदाहरण के लिए, हत्या के मुकदमे में, जिसमें प्रतिवादी आत्मरक्षा के लिए बचाव का सहारा लेता है। (2) जब प्रतिवादी स्वचालितता की दलील देता है, तो साक्ष्य का बोझ उस पर होता है। (3) जब प्रतिवादी पागलपन की दलील देता है, तो साक्ष्य और प्रेरक दोनों बोझ उस पर आ जाते हैं। इस मामले में,'...हालाँकि, यह पर्याप्त है अगर वह संभावनाओं के संतुलन पर अपना मामला साबित करता है (यानी उसे जूरी को राजी करना होगा कि यह अधिक संभावना है कि वह सच बोल रहा है न कि नहीं) (4) कुछ मामलों में स्पष्ट रूप से क़ानून प्रतिवादी पर प्रेरक बोझ डालता है; उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो सार्वजनिक रूप से आक्रामक हथियार रखता है, वह अपराध

का दोषी है जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि उसके पास इसे ले जाने के लिए वैध अधिकार या उचित बहाना था।

14. जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी और आईपीसी की धारा 304 बी को उनके संबंधित क़ानूनों में एक साथ पेश किया गया था और इसलिए, आमतौर पर यह माना जाना चाहिए कि संसद ने जानबूझकर धारा 304 बी में 'डीम्ड' शब्द का इस्तेमाल किया है। इस प्रावधान को दूसरों से अलग करें। हालाँकि, वास्तविकता में, इन प्रावधानों को एक समझदार और कानूनी रूप से स्वीकार्य अर्थ देना लगभग असंभव है, जब तक कि 'दिखाया गया' शब्द का उपयोग 'साबित' के पर्याय के रूप में और 'अनुमान' शब्द का उपयोग 'माने गए' शब्द के साथ स्वतंत्र रूप से विनिमेय के रूप में नहीं किया जाता है। '. नागरिक और राजकोषीय कानून के दायरे में, परिस्थितियों के एक समूह को दर्शाने के लिए 'डीम' शब्द के सामान्य अर्थ को आयात करना मुश्किल नहीं है, जिसे वास्तव में जो है उसके विपरीत माना जाता है। हालाँकि, आपराधिक कानून में, इस दृष्टिकोण को रटकर अपनाना अरुचिकर है। हमारे पास त्रावणकोर-कोचीन राज्य बनाम शनमुघा विलास कैश्यूनट फैक्ट्री एआईआर 1953 एससी 333 और तमिलनाडु राज्य बनाम अरूरन शुगर्स लिमिटेड (1997) 1 एससीसी 326 दोनों मामलों में इस न्यायालय की संविधान पीठ का उच्च अधिकार है, जिसमें न्यायालय को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। 'डीम्ड' शब्द के प्रयोग द्वारा लाई गई वैधानिक कल्पना के पीछे का उद्देश्य कानून को पूर्ण प्रभाव देना और उसे उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना है। हम यह जोड़ सकते हैं कि आम तौर पर यह माना जाता है कि खंडन योग्य के साथ-साथ अपरिवर्तनीय भी होते हैं। अनुमान, बाद वाले अक्सर किसी प्रावधान के माध्यम से कृत्रिमता को वास्तविकता मान लेते हैं। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी ठहराना आपराधिक न्यायशास्त्र के लिए घृणित है, भले ही उसका अपराध करने का न तो इरादा

था और न ही अपराध करने में सक्रिय भागीदारी थी। गहन विचार-विमर्श के बाद हम धारा 304 बी में 'दिखाए गए' शब्द का अर्थ लगाना अनिवार्य मानते हैं। आईपीसी का, वास्तव में, 'साबित' करना है। दूसरे शब्दों में, यह साबित करना अभियोजन पक्ष का काम है कि 'दहेज मृत्यु' हुई है, अर्थात्, (i) कि एक महिला की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में उसके जलने या शारीरिक रूप से घायल होने के कारण हुई है, (ii) शादी के सात साल के भीतर, (iii) और वह अपने पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार हुई थी, (iv) दहेज की किसी भी मांग के संबंध में और (v) यह क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था दहेज की मांग के साथ उसका कारणात्मक संबंध या जीवंत संबंध बना रहा। हम जानते हैं कि 'जल्द' शब्द धारा 304 बी में जगह पाता है; लेकिन हम इसके उपयोग की व्याख्या दिनों या महीनों या वर्षों के संदर्भ में नहीं करना चाहेंगे, बल्कि आवश्यक रूप से यह इंगित करते हुए करना चाहेंगे कि दहेज की मांग पुरानी या अतीत की भूल नहीं होनी चाहिए, बल्कि धारा 304 बी के तहत मृत्यु का निरंतर कारण होनी चाहिए। आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या। एक बार जब अभियोजन पक्ष द्वारा इन सहवर्ती लोगों की उपस्थिति स्थापित या दिखा दी जाती है या साबित कर दी जाती है, यहां तक कि संभावना की प्रबलता से भी, निर्दोषता की प्रारंभिक धारणा को आरोपी के अपराध की धारणा से बदल दिया जाता है, जिसके बाद सबूत का भारी बोझ उस पर स्थानांतरित हो जाता है और उससे आवश्यकता होती है उचित संदेह से परे उसके अपराध को खारिज करने वाले सबूत पेश करने के लिए। हमें ऐसा लगता है कि 'डीम्ड' शब्द का इस्तेमाल करने से संसद का इरादा यह था कि केवल सबूतों की प्रचुरता ही पति या उसके परिवार के सदस्यों को उनके अपराध से मुक्त करने के लिए अपर्याप्त होगी। यह व्याख्या अभियुक्तों को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका प्रदान करती है। यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 का भी अभिधारणा है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी

और आईपीसी की धारा 304 बी का उद्देश्य, हमारी राय में, शादी के सात साल के भीतर किसी महिला की आत्महत्या या मृत्यु के मामले में सबूतों की कमी या अनुपस्थिति का मुकाबला करना है। यदि "दिखाया गया" शब्द को उसका सामान्य अर्थ देना है तो अभियोजन पक्ष को केवल अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। यह आवश्यक नहीं है कि अदालत में मौखिक बयान दिया जाए, और उसके बाद अभियुक्त को अभियोजन पक्ष द्वारा अनुसरण किए जाने वाले विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं। यह प्रक्रिया सामान्य कानून प्रणालियों के लिए अज्ञात है, और सीआर.पी.सी. के चिंतन से परे है।

15. संविधान पर स्थापित कानूनी व्यवस्था में किसी व्यक्ति के अपराध को मानने वाले प्रावधान की चौड़ाई और आयाम पर संक्षेप में विचार करने की आवश्यकता है। संविधान वह आधार है जिस पर कानूनी ढांचा खड़ा किया जाना है और पूरे ढांचे के जमीन पर गिरने के डर से इसकी नींव को कमजोर नहीं किया जा सकता है। यदि संविधान स्पष्ट रूप से किसी विशेष स्थिति की पुष्टि या निषेध करता है, तो सभी वैधानिक प्रावधान जो उसके साथ असंगत हैं, उन्हें अधिकारातीत माना जाना चाहिए और इसलिए, उनका पालन नहीं किया जाना चाहिए। हम इसे पहले ही नोट कर चुके हैं हमारे संविधान का अनुच्छेद 20 निर्दोषता की धारणा की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाता है, जिससे यह संसद पर छोड़ देता है कि जब भी आवश्यक या समीचीन लगे तो इसे अनदेखा कर दे। एक गहन जांच से पता चलता है कि कुछ कानूनी सिद्धांत जैसे कि निर्दोषता का अनुमान बहुत व्यापक कानूनी प्रणाली में पाया जा सकता है, सर्वव्यापी सामान्य कानून प्रणाली में, और नागरिक कानून प्रणाली में प्रतिबंधात्मक रूप से। हमें ऐसा लगता है कि निर्दोषता का अनुमान एक ऐसा कानूनी सिद्धांत है जो आम कानून के प्रति निष्ठा के कारण कई देशों के कानूनी ढांचे का विस्तार करता है; यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भी उस पर अपनी मुहर लगाता है।

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 11.1 में कहा गया है - "दंडात्मक अपराध के आरोप वाले प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक परीक्षण में कानून के अनुसार दोषी साबित होने तक निर्दोष मानने का अधिकार है, जिसमें उसके पास अपनी रक्षा के लिए आवश्यक सभी गारंटी हैं। " नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, 1966 का अनुच्छेद 14(3)(जी), न्यूनतम गारंटी के रूप में आश्वासन देता है कि हर किसी को यह अधिकार है कि उसे अपने खिलाफ गवाही देने या अपराध कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए यूरोपीय कन्वेंशन का अनुच्छेद 6, सबसे पहले निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का वादा करता है और दूसरा, आश्वासन देता है कि किसी भी व्यक्ति पर आपराधिक अपराध का आरोप लगाया जाएगा, जब तक कि वह कानून के अनुसार दोषी साबित न हो जाए, उसे निर्दोष माना जाएगा। हम तुरंत उस अनुमानित निर्दोषता के सिद्धांत पर जोर दे सकते हैं हमेशा इसके विपरीत स्पष्ट कानून का मार्ग प्रशस्त करेगा। कुछ परिस्थितियों में निर्दोषता की धारणा को भी बुनियादी मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। हालाँकि, संसद को असंख्य प्रतिस्पर्धी, यदि परस्पर विरोधी नहीं, तो सामाजिक हितों का पता लगाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दुल्हन को जलाने की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि से परेशान होकर, संसद ने उन मामलों में सबूत के विपरीत सबूत का बोझ पति और उसके रिश्तेदारों पर डालना विवेकपूर्ण, समीचीन और अनिवार्य समझा। दर्शाया गया है कि दहेज हत्या हुई है। किसी अभियुक्त की बेगुनाही की धारणा में घुसपैठ या कमजोर पड़ने को, यहां तक कि उसकी वैधानिक मंजूरी के आधार पर, उन मामलों में न्यायालयों द्वारा मान्यता दी गई है जहां मृत्यु ऐसे घर में होती है जहां केवल दूसरा पति या पत्नी मौजूद होता है; साथ ही जहां किसी व्यक्ति को आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया हो। इसलिए धारा 304 बी में अपमानजनक प्रावधान हमारे आपराधिक

कानून न्यायशास्त्र में न तो कोई नवीनता है और न ही अभिशाप है। [मीर मोहम्मद उमर और सुब्रमण्यम बनाम तमिलनाडु राज्य (2009) 14 एससीसी 415 देखें।

16. यह पहले ही बताया जा चुका है कि हमारे ही विद्वान भाई द्वारा लिखित, पठान हुसैन बाशा के साथ-साथ अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य 2010 (12) धारा 350 में, धारा 304 बी में "दिखाया गया" शब्द का उपयोग किया गया है। स्पष्ट रूप से इसे उचित महत्व नहीं दिया गया है क्योंकि इसे "साबित" शब्द द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रतिस्थापित किया गया है। नल्लमवीरा स्टेयानंदम बनाम लोक अभियोजक 2004 (10) एससीसी769 मामले में इसके विपरीत, यह राय दी गई है कि "इस मामले में बचाव पक्ष को अदालत को संतुष्ट करना है कि दहेज की मांग और उत्पीड़न के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले के बावजूद, मौत मृतक की घटना इस वजह से नहीं हुई है और यह ऐसी दहेज की मांग या उत्पीड़न से बिल्कुल अलग कारण से हुई है।"

17. इस परिप्रेक्ष्य में कि संसद ने अनाकार सर्वनाम/संज्ञा "इट" (जिसे हम सोचते हैं कि इसे अभियोजन पक्ष के संकेत के रूप में समझा जाना चाहिए) का उपयोग किया है, इसके बाद धारा 304 बी में "दिखाया गया" शब्द का उपयोग किया गया है, व्याख्या करने का उचित तरीका धारा यह है कि "दिखाया गया" को "साबित" के अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए और "माना गया" शब्द को "अनुमानित" के अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए। न तो जीवन और न ही स्वतंत्रता को कमज़ोर किया जा सकता है

व्यक्ति को निवारणात्मक या दोषमुक्त करने वाली परिस्थितियों का खुलासा करने का अवसर प्रदान किए बिना। यही कारण है कि इस न्यायालय ने मिठू बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1983 एससी 473 में अपने शानदार फैसले में आईपीसी की धारा 303 में अनिवार्य मौत की सजा को रद्द कर दिया। इसलिए, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत का भार पति पर पड़ता है। उसके समझे गए दोषी को

खारिज करना, और यह कि इससे पहले अभियोजन पक्ष को केवल तीन कारकों की उपस्थिति साबित करनी होगी, अर्थात (i) असामान्य परिस्थितियों में एक महिला की मृत्यु (ii) भीतर उसकी शादी के सात साल, और (iii) और यह कि मृत्यु का दहेज की किसी भी मांग से जुड़ी क्रूरता से सीधा संबंध था। दूसरा पहलू यह है कि पति के कंधों पर वास्तव में एक भारी बोझ है, जिसमें उसकी समझी गई दोषी को उचित संदेह से परे विस्थापित और पलटना होगा। यह स्पष्ट रूप से उस तरीके के रूप में सामने आता है जिस तरीके से संसद चाहती थी बड़े पैमाने पर दुल्हन को जलाने या दहेज हत्या के संकट और बुराई को दूर करें, जिस तरीके से हम बिना शर्त सदस्यता लेते हैं। लापरवाही से बचने के लिए हम दर्ज करेंगे कि कानून की हमारी समझ को पी.एन. कृष्ण लाल बनाम केरल सरकार, 1995 सप्लिमेंट (2) एससीसी 187 में इस न्यायालय के एक अत्यंत व्यापक और विद्वतापूर्ण फैसले में समर्थन मिलता है, जिसमें फैसले दुनिया भर में फैले हुए हैं। उल्लेख एवं चर्चा की गई है। यह उजागर करना भी महत्वपूर्ण है कि धारा 304 बी में आरोपी को अपने खिलाफ सबूत देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके समझे गए अपराध को उचित संदेह से परे हटाने का कठिन बोझ डाला गया है। हमारी राय में, पति की जिम्मेदारी को कम करना उचित नहीं होगा। संभाव्यता की प्रधानता, क्योंकि यह धारा 304 बी में व्यक्त किए गए समझे गए अपराध को नष्ट कर देगी, और इस तरह की क्यूरी व्याख्या संसद के इरादों और उद्देश्यों को पराजित और बेअसर कर देगी। एक परिदृश्य जो तुरंत दिमाग में आता है वह यह है कि जहां आरोपी पति द्वारा दहेज की मांग निश्चित रूप से की गई थी, जहां पत्नी ने उत्तेजित स्थिति में अपना वैवाहिक घर छोड़ने का फैसला किया था, और जहां अपने माता-पिता के घर जाने के लिए बस से यात्रा करते समय बस के साथ हुई दुर्घटना में वह बुरी तरह झुलस गई। निश्चित रूप से, यदि पति यह साबित कर दे कि दुर्घटना में उसकी कोई भूमिका नहीं है, तो उसे अपनी पत्नी की मृत्यु का कारण नहीं माना जा सकता। यह तुरंत

स्पष्ट करने की जरूरत है कि अगर पत्नी ने बस के सामने या ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी होती, तो पति के पास कोई बचाव नहीं होता। उदाहरण सेना हो सकते हैं, और इसलिए हम आगे जाने से बचेंगे। कहने की आवश्यकता केवल यह है कि यदि पति ऐसे तथ्य साबित करता है जो उचित संदेह से परे दर्शाते हैं कि वह अपनी पत्नी की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट से नहीं कर सकता था या असामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु में किसी भी तरह से शामिल नहीं था, तो वह ऐसा नहीं करेगा। धारा 304 बी के तहत दोषी ठहराया जा सकता है।

18. अब, हाथ में आए मामले पर। हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है, जैसा कि नीचे की दोनों अदालतों के समक्ष भी असफल रूप से तर्क दिया गया था कि एफआईआर दर्ज करने में 'देरी' हुई थी। समवर्ती विचारों में कोई विकृति नहीं है कि त्रासदी के अगले दिन, यानी 8/02/98 को दस घंटे के बाद दर्ज करना अत्यधिक देरी का गठन नहीं करता था, जैसे कि उचित रूप से एफआईआर को बाद में सोचा गया या काल्पनिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। शिकायतकर्ता को परिवार और दोस्तों के साथ दूसरे गांव की यात्रा करनी थी, उसे एफआईआर दर्ज करने से पहले त्रासदी के बारे में पूछताछ करनी होगी और परिस्थितियों पर विचार करना होगा। यह तर्क भी उतना ही बेतुका है कि एक बार जब उच्च न्यायालय ने अन्य आरोपियों, दविंदर सिंह (देवर) और जरनैल सिंह (ससुर) को बरी करना उचित समझा, तो पति/अपीलकर्ता को भी इसी तरह बरी कर दिया जाना चाहिए था। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आरोपी अपने माता-पिता और भाई के साथ नहीं रह रहा था, और पति के परिवार के सदस्यों को फंसाने के लिए मजबूत सबूत की आवश्यकता होना उचित नहीं है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा हम पर यह प्रभाव डालने के लिए निबंध लिखा गया है कि इस प्रावधान में बताई गई क्रूरता "उसकी मृत्यु से तुरंत पहले" घटित नहीं हुई थी। यह तर्क, एक आपत्ति पर, वैधानिक क्रूरता मानता है वास्तव में, प्रतिबद्ध किया गया था। मृतक

और अपीलकर्ता की शादी फरवरी, 1997 में हुई थी और अपीलकर्ता ने एक वर्ष के भीतर आत्महत्या कर ली थी; यहां तक कि यह अनुमान लगाने के लिए कि यह मृत्यु से ठीक पहले नहीं था, केवल यह कहा जाना चाहिए कि इसे सख्ती से मार गिराया जाएगा।

19. अंततः हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या अभियोजन ने सफलतापूर्वक 'दिखाया' है कि मृतक के साथ क्रूरता की गई थी जो दहेज की मांग से जुड़ी थी। हम यहां उपयोगी रूप से दोहरा सकते हैं कि परिप्रेक्ष्य में "साबित" के बजाय "दिखाया गया" के उपयोग को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य की प्रबलता के आधार पर उत्तरदायित्व संतुष्ट होगा।

20. अभियोजन पक्ष के दो गवाह, जिन पर पूरा प्रकरण आधारित है, पीडब्लू 4 और पीडब्लू7 हैं। शिकायतकर्ता पी डब्ल्यू 4-अंगरेज़ सिंह परिवार में सबसे बड़े प्रतीत होते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके भाई, यानी मृतक के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि विवाह के समय पर्याप्त कन्यादान दिया गया था; अपनी मृत्यु से दो महीने पहले, मृतिका ने उनके घर जाकर अपने भाइयों को बताया था कि उसका पति और उसका परिवार उसे दहेज, विशेषकर मोटरसाइकिल और फ्रिज के लिए परेशान कर रहा था। इन माँगों के बारे में जानने पर पी डब्ल्यू4 ने उससे कहा था कि ये सामान आएगा उसके भाइयों की शादी के समय प्रदान किया जाए। पीडब्लू4 को राजवंत सिंह ने बताया कि उसकी भतीजी ने आत्महत्या कर ली है। शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया है कि सगाई या शादी के समय दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। उसके मामा गुरदीप सिंह ने कथित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण शादी तय/मध्यस्थता/व्यवस्था की, फिर भी उन्हें अंग्रेज सिंह द्वारा दहेज की मांगों के बारे में अवगत नहीं कराया गया। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि दहेज की इन मांगों के संबंध में कोई पंचायत बुलाई गई थी, जबकि मृतक के सगे भाई सुखवंत सिंह पीडब्लू 7 ने जिरह में

स्पष्ट रूप से कहा है कि अंग्रेज सिंह और गुरदीप सिंह और कई अन्य लोगों की एक पंचायत ने विचार-विमर्श किया था।

21. जिरह में, शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि मृतिका ने अपनी घरेलू समस्याओं के बारे में या आरोपी द्वारा दहेज की मांग के बारे में कभी भी उससे बात नहीं की, सिवाय एक बार, अपनी यात्रा के आखिरी अवसर पर। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि उसके भाइयों ने भी इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पीडब्लू4 ने कहा कि वह 7.2.1998 को शाम लगभग 7.00 बजे उस गाँव में पहुँचे जहाँ मृतिका रहती थी और जहाँ उसने आत्महत्या कर ली थी और तथ्यों का पता लगाने के बाद वह तुरंत कई अन्य लोगों के साथ उस स्थान के लिए रवाना हो गया; अगली सुबह उन्होंने थाना असंध में रिपोर्ट दर्ज कराई। उनके बयान से महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने दहेज की केवल एक कथित मांग के बारे में गवाही दी है।

22. मृतक के सगे भाई सुखवंत सिंह से पीडब्लू 7 के रूप में पूछताछ की गई है और उसने गवाही दी है कि मृतक अपनी मृत्यु से दो महीने पहले उनके घर आया था और बताया था कि अपीलकर्ता, उसका छोटा भाई, उनके पिता और मां परेशान करते थे और वे उसे प्रताड़ित करते थे और मोटरसाइकिल और फ्रिज के रूप में दहेज की मांग करते थे और उन्होंने ये बातें उनके चाचा अंग्रेज सिंह और अपने बड़े भाईजसवंत सिंह को भी बता दी थीं। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मृतक को उनकी वित्तीय कठिनाइयों के बारे में समझाया और उसकी और उसके भाई की शादी के बाद मोटरसाइकिल और फ्रिज देने का वादा किया। उन्हें अंग्रेज सिंह/पीडब्लू4 द्वारा 7.2.98 को मृतक की मृत्यु की सूचना दी गई थी। जिरह में इस गवाह ने भी स्वीकार किया है कि शादी से पहले या शादी के समय दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। उन्होंने एक पंचायत के बारे में भी गवाही दी है जिसमें गुरदीप सिंह (मामा) के साथ-साथ अंग्रेज सिंह/पीडब्लू4 भी शामिल थे, जिन्होंने, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, स्पष्ट रूप से कहा है कि

ऐसी कोई पंचायत नहीं हुई थी। अपीलकर्ता का कथन उसके सामने रखा गया और उसे अस्वीकार कर दिया गया, अर्थात्, मृतक गुस्सैल था, वह उससे अपने बाल मुंडवाना चाहता था, उसे अपने माता-पिता से अलग रहने के लिए मजबूर करता था, चाहता था कि वह कमल के पास चले जाए और एक व्यवसाय शुरू करे, ये सभी बातें थीं उसकी इच्छा के विरुद्ध. मूलभूत और महत्वपूर्ण प्रश्न जो न्यायालय को खुद से पूछना है और इसका ठोस उत्तर ढूंढना है, वह यह है कि क्या ये साक्ष्य प्रमुख रूप से यह साबित करते हैं कि अपीलकर्ता ने दहेज की मांग को लेकर मृतिका के साथ क्रूरता का व्यवहार किया था। यदि उत्तर सकारात्मक है तो ही न्यायालय को उचित संदेह से परे उसके दोषी अपराध की धारणा को बरी करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन करना होगा।

हमने इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया है कि आत्महत्या के समय मृतक गर्भवती थी और केवल असाधारण और जबरदस्त कारकों ने ही उसे अपने अजन्मे बच्चे के साथ अपनी जान लेने के लिए प्रेरित किया होगा। तथ्य यह है कि उसने ऐसा किया। उसे यह चरम और भयावह कदम उठाने के लिए किसने प्रेरित या मजबूर किया यह एक रहस्य बना रहेगा, क्योंकि हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है या दिखाया भी है कि दहेज की मांग को लेकर उसके साथ इतनी क्रूरता की गई, जिसके कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ी। सामान्य तौर पर दहेज की माँगें तब व्यक्त की जाती हैं जब विवाह पर सहमति हो जाती है और निश्चित रूप से विवाह के समय भी दोहराई जाती है और ऐसी माँगें विवाह के कुछ वर्षों तक जारी रहती हैं। सामान्य तौर पर, यदि किसी महिला पर अत्याचार और उत्पीड़न किया जा रहा है, तो वह इस स्थिति से पीछे नहीं हटेगी और निश्चित रूप से बार-बार अपने परिवार को सूचित करेगी। ऐसा खासतौर पर इससे पहले होता है कि वह अपनी जान लेने जैसा चरम कदम उठा ले। इसमें पंचायत के संबंध में पीडब्लू4 और पीडब्लू7 के

बयानों और गुरदीप सिंह की उपस्थिति और ज्ञान के बीच विसंगतियां और विरोधाभास भी शामिल हैं। इन्हीं कारणों से हमारी राय है कि अभियोजन पक्ष ने संभावनाओं की प्रबलता से भी यह नहीं दिखाया/प्रस्तुत किया है या साबित नहीं किया है कि मृतक के साथ दहेज की मांग से उत्पन्न या उसके आधार पर क्रूरता का व्यवहार किया गया था। यह संभावना है कि एल्यूमीनियम फॉस्फेट का अंतर्ग्रहण आकस्मिक हो सकता है।

23. हम केवल यह देख सकते हैं कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपनी परीक्षा में अभियुक्त ने अपने बचाव का विवरण पेश किया है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां उन्होंने अदालत द्वारा उनसे पूछे गए सभी सवालों से इनकार कर दिया हो। जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, अभियोजन पक्ष द्वारा दिखाए गए तथ्यों या परिस्थितियों की अपर्याप्तता या असंतोषजनक प्रकृति के कारण, वर्तमान मामले में, अपनी बेगुनाही साबित करने का बोझ अपीलकर्ता पर नहीं डाला गया है।

24. इस विश्लेषण में, अपील की अनुमति दी जाती है और अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और दंडित करने वाले फैसले को खारिज कर दिया जाता है।

निधि जैन

अपील स्वीकार की गई

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।